International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एवं युवा राजनीति का रचनात्मक शक्ति पर प्रभाव

प्रो. गोपाल प्रसाद[1], रोहित कुमार सिंह[2], विशाल गुप्ता[3]

[1]वरिष्ठ आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
[2,3]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

सारांश:
विश्व में भारत की पहचान सबसे युवा देश के रूप है तथा उत्तर प्रदेश अपनी विशाल युवा आबादी के कारण देश की सामाजिकए आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाये हुए है। युवा शक्ति को किसी भी समाज का भविष्य, विकास, नवाचार, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन का वाहक माना जाता हैए किन्तु जब यही युवा वर्ग बेरोजगारीए शासकीय उदासीनताए असमान अवसरए संसाधनों की पहुंच से दूर, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंबन एवं परीक्षा अनियमितताओं आदि समस्याओं से पीड़ित रहता हैए तब ऐसे में उसकी ऊर्जा सामाजिक एवं राजनीतिक असंतोषए राजनीति के ध्रुवीकरणए अलगावए निराशा एवं कुंठा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, बल्कि सामाजिक गतिशीलताए राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं विकास को भी आघात पहुँचता है। इस प्रकार, बेरोजगारी न सिर्फ एक आर्थिक समस्या है, बल्कि यह **सामाजिक बेरोजगारी एवं राजनीतिक बेरोजगारी** को जन्म देता है। प्रस्तुत शोध.पत्र उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में, बेरोजगारी का आर्थिक एवं सामाजिक दुष्प्रभाव की अपेक्षा राजनीतिक दुष्प्रभाव पर अध्ययन प्रस्तुत करता है अर्थात यह लेख 'बेरोजगारी का राजनीतिक समाजशास्त्रीय या 'राजनीतिक व्यवहारवादी' अध्ययन प्रस्तुत करता है। साथ ही चूंकि बेरोजगारी का संबंध युवाओं से हैं, ऐसे में प्रदेश की युवा राजनीति के स्वरूप का अध्ययन करते हुए इन दोनों पहलुओं का प्रदेश के रचनात्मक शक्ति पर पडने वाले प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन के माध्यम से इस बात को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है कि बेरोजगारी केवल आर्थिक समस्या नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं नागरिक समाज की रचनात्मक शक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। यह अध्ययन साहित्य समीक्षा के माध्यम से रचनात्मक शक्ति का बेरोजगारी एवं युवाओं की सक्रियता से संबंधी अध्ययन एवं प्रदेश में छात्र केंद्रित राजनीति के ऐतिहासिक संदर्भए हाल के वर्षों में राज्य में हुए विभिन्न युवा केन्द्रित जन आंदोलनए बेरोजगारी से उत्पन्न मानसिक असंतोष एवं विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों का अध्ययन करते हुए उसका विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत अध्ययन **गुणात्मक** प्रकार का है एवं **द्वितीय स्रोतों** पर आधारित आधारित हैए इसमें स्रोत के रूप में विभिन्न सरकारी एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नीति आयोग, गैर सरकारी संगठनों के आंकड़ोंए शोध.पत्र, समाचार.पत्र, युवा आंदोलन केन्द्रित साहित्य एवं रचनात्मक शक्ति की अवधारणा को समझने के लिए विभिन्न विद्वानों के पाठ्यपुस्तकों को शामिल किया गया है।

मूल शब्द. रचनात्मक शक्ति, बेरोजगारी, युवा राजनीति, लोकतंत्र, नागरिक समाज, सामूहिक कार्रवाई, उत्तर प्रदेश, राजनीतिक गतिशीलता, राजनीतिक उद्यमिता।

प्रस्तावना:

वर्तमान में भारत विश्व का सबसे युवा लोकतंत्र है। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश लिए हुए है। जहां न सिर्फ सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, बल्कि 15-35 आयु वर्ग के युवा शक्ति का बड़ा केंद्र भी है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक है जिसकी विशाल जनसंख्या राज्य की सबसे बड़ी संपत्तियों में है। यह न केवल वृहद मानव संसाधन प्रदान करती है अपितु जनसंख्या की सामाजिकए आर्थिक विविधता के कारण कौशल, संस्कृति और उपभोक्ता मांग का एक उपयुक्त मिश्रण भी तैयार करती है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य की जनसंख्या 19.8 करोड़ थी।[1] मार्च 2026 हेतु अनुमानित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 29.19 करोड़ है जो भारत की कुल जनसंख्या 141.51 करोड़ का लगभग 17.8% और विश्व की जनसंख्या 830 करोड़ का लगभग 3.0% है; भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में लगभग 17% योगदान है। यदि उत्तर प्रदेश एक स्वतंत्र प्रदेश होता तो मार्च 2026 में उसकी अनुमानित जनसंख्या 25ण्19 करोड़ के साथ वह विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद पाँचवें स्थान पर आता।[2]

तालिका 1रू विश्व जनसंख्या विन्यास 2026 (करोड़ में)

क्षेत्र	जनसंख्या (करोड़)	विश्व के कुल जनसंख्या में प्रतिशत (%)
विश्व (भारत के बिना)	688.49	83
भारत (उत्तर प्रदेश के बीना)	116.32	14
उत्तर प्रदेश	25.19	3
विश्व	830.00	100

स्रोतरू उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26

तालिका 2 रू उत्तर प्रदेश की जनसँख्या के अनुमान (करोड़)

वर्ष	जनसंख्या (करोड़)	पिछली अवधि से वृद्धि (करोड़)	वृद्धि प्रतिशत (%)
2011	19.98	-	-
2026	25.19	5.21	26.08
2031	26.65	1.46	5.80
2036	27.83	1.18	4.43
2041	28.87	1.04	3.74
2046	29.84	0.97	3.36
2051	30.72	0.88	2.95

स्रोत: उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2025-26

राजनीतिक दृष्टि से देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश का संसद में जनता के सदन लोकसभा में 80ए उच्च सदन राज्यसभा में 31 सीटें है, जबकि राज्य के विधानमंडल के निचले सदन

विधानसभा में 403 तथा द्विसदनीय राज्यों की श्रेणी में शामिल प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य संख्या 100 है। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश को केंद्र की सत्ता का सबसे महत्त्वपूर्ण राज्य माना जाता है; जो इसे भारतीय संघीय लोकतंत्र का सबसे प्रभावशाली राज्य बनाता है। राष्ट्र की राजनीति में सत्ता परिवर्तन से लेकर सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में उत्तर प्रदेश की भूमिका निर्णायक रही है। प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रवृत्तियाँ प्रायः राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करती है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर समकालीन भारतीय राजनीति तक अनेक राष्ट्रीय नेता एवं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते आए हैं। उत्तर प्रदेश से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौथे चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन किया, साथ ही उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं नरेंद्र मोदी है।

भारत अपनी विविधता के लिए विश्व। में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश सामाजिक दृष्टि से भी विविधताओं से भरा हुआ राज्य है; जातीय, धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय विविधता के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी समाज के बीच विविधता देखने को मिलती है। सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, लैंगिक समानता, क्षेत्रीय असमानता, सामाजिक गतिशीलता जैसे विषय प्रदेश की राजनीति और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करते हैं। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME), सेवा क्षेत्र, पर्यटन और संरचना विकास आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है तथा औद्योगिक निवेश, एक्सप्रेसवे, रक्षा औद्योगिक गलियारा, डेटा सेन्टर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP), स्टार्टअप इंडिया और सोशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया।

बेरोजगारी का राजनीतिक समाजशास्त्र:

सामान्यतः बेरोजगारी को एक आर्थिक समस्या के रूप में देखा जाता है, किन्तु अध्ययन के राजनीतिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के अनुसार यह केवल श्रम बाजार की समस्या ही नहीं है, अपितु बेरोजगारी का राज्य, समाज और नागरिकों पर पड़ने वाले प्रभाव का बहुआयामी अध्ययन है। **किसी भी समाज में शिक्षित एवं कार्य करने वाले इच्छुक युवाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है एवं उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार नहीं उपलब्ध होताए ऐसे में इसका प्रभाव केवल आर्थिक और उत्पादन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह सामाजिक विश्वास, राजनीतिक भागीदारी, लोकतांत्रिक संस्थाओं में सत्ता की वैधता तथा राज्य के उत्तरदायित्व क्षमता को भी प्रभावित करता है।**[3] राजनीतिक समाजशास्त्र इस बात पर जोर देता है कि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और अवसरों का असंतुलित वितरण नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। रोजगार ना सिर्फ आजीविका का साधन है बल्कि यह आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नागरिक भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विश्वास का भी आधार स्तंभ है, यही कारण है कि जब रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं अथवा भर्ती. प्रक्रियाओं में अनिश्चितता, विवाद या विलंबन की समस्या आती है तो ऐसे में नागरिकों के भीतर असंतोष उत्पन्न होता है जो सामाजिक कुंठा को जन्म देता हैं। यही असंतोष अनेक लोकतांत्रिक आंदोलनों, छात्र राजनीति, सार्वजनिक विरोध नीतिगत सुधारों आदि की मांग के रूप में सामने आता है।[4] ए.आर. देसाई ने भारत में आर्थिक विकास की चार समाजशास्त्रीय समस्याएं बताई हैं। (1) पुराने सामाजिक संगठन का बदल जाना और सामाजिक संबंधों के नए ताने बाने का उदय, (2) पुरानी सामाजिक संस्थाओं में सुधार या तिलांजलि और नई प्रकार की सामाजिक संस्थाओं का विकास करना, (3) सामाजिक नियंत्रण के पुराने स्वरूपों को बदलना या हटाना और

नए प्रकार की सामाजिक शक्ति का सृजन होनाए और (4) सामाजिक परिवर्तन के पुराने स्रोतों का समापन या उन पर पुनर्विचार और सामाजिक परिवर्तन के लिए नए उपायों और कारकों का निर्धारण।[5]

पिछले कई दशकों में उत्तर प्रदेश की आर्थिक संरचना का संक्रमण तो हुआ किन्तु रोजगार सृजन की गति उस अनुपात में नहीं बढ़ी। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, जबकि उद्योगों की कमी और सेवा क्षेत्र में सीमित अवसरों के कारण शिक्षित बेरोजगारी एक भयावह रूपधारण कर चुका है। Periodic Labour Force Survey (PLFS 2022-23) के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का कुल दर लगभग 2.4: के आसपास रही है, 15-29 वर्ष आयु में यह दर लगभग 6-7% तक देखी गई। है। शहरी क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया गया है, जो इस बात का संकेत देता है कि समस्या केवल रोजगार की उपलब्धता तक ही नहीं बल्कि रोजगार की गुणवत्ता और कौशल का भी है। प्रदेश में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण आयाम शिक्षित बेरोजगारी है। युवा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद, बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के समीप व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। प्रतियोगिता अत्यधिक तीव्र होने के कारण एवं भर्ती परीक्षाओं में विलंबन, परीक्षा पत्र. लीक, न्यायिक विवाद एवं नियुक्तियों में देरी आदि घटनाएं युवाओं में असंतोष को जन्म देती है। यह समस्या केवल प्रशासनिक नहीं रह जाती बल्कि लोकतांत्रिक शासन की भी विश्वसनीयता से भी जुड़ा प्रश्न बन जाती है।

सामाजिक दृष्टि से दीर्घकालिक बेरोजगारी समाज में अनेक गंभीर समस्या को जन्म देती है, जिससे युवाओं में आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक तनाव, सामाजिक हताशा, पारिवारिक निर्भरता सामाजिक कुंठा, भविष्य के प्रति अनिश्चितता जैसे घटनाओं में वृद्धि होती है। आर्थिक दृष्टि से बेरोजगारी न सिर्फ राज्य की उत्पादक क्षमता को सीमित करती है, जबकि शिक्षित एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते, ऐसे में मानव पूंजी का उपयोग नहीं हो पाता; जो आय, उत्पादकता, उपभोग, निवेश तथा राज्य के समग्र आर्थिक विकास पर प्रतिकूल असर डालता है। क्षमता दृष्टिकोण सिद्धांत के अनुसार विकास का वास्तविक अर्थ केवल आय में वृद्धि नहीं बल्कि व्यक्तियों की क्षमताओं एवं अवसरों का विस्तार भी है यदि युवा अपनी शिक्षा और कौशल क्षमता का उपयोग ही न कर सकेंए ऐसे में यह केवल आर्थिक हानि नहीं होगी बल्कि मानव विकास की भी क्षति है।[6] यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बेरोजगारी राज्य और नागरिकों के बीच उत्तरदायित्व के प्रश्न को भी उजागर करता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज सरकार से केवल रोजगार उपलब्धता की अपेक्षा नहीं करताए अपितु निष्पक्षए पारदर्शी एवं समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया का भी अपेक्षा करता है। ऐसे में जब ऐसी अपेक्षा पूर्ण नहीं होती तो लोकतांत्रिक विरोध, जनमत निर्माण, छात्र आंदोलन, सार्वजनिक विमर्श आदि के माध्यम से सरकार पर दबाव पड़ता है इस प्रकार देखा जाए तो बेरोजगारी लोकतांत्रिक राजनीति का सक्रिय मुद्दा बन जाता है।

युवा राजनीति और लोकतांत्रिक सहभागिता:

किसी देश एवं समाज में राजनीति आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक कारक उत्तरदायी होते हैंय जैसे समाज में विविध संस्थाओं एवं संरचनाओं का स्वरूपए जनमानस का सामर्थ्यए राजनैतिक स्थिरता, सांस्कृतिक विरासत और राजनैतिक स्वरूप आदिए जो राष्ट्र या प्रदेश के विकास और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में युवा सबसे गतिशील, ऊर्जावान एवं परिवर्तनकारी सामाजिक शक्ति मानी जाती है। राष्ट्र का भविष्य केवल आर्थिक गतिशीलता एवं प्रगति पर निर्भर नहीं करताए अपितु इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके युवा सार्वजनिक जीवन, लोकतांत्रिक संस्थाओं, नीति.निर्माण की प्रक्रियाओंए सामाजिक गतिविधियों में किस प्रकार की भागीदारी निभाते हैं। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों से निर्धारित नहीं होतीए बल्कि नागरिको. विशेषकर युवाओं की सक्रिय राजनीतिक सहभागिता, आलोचनात्मक चेतना एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व की भावनाओं आदि पर आधारित होती है।[7] भारत में वर्तमान राजनैतिक अभिजन अपने स्वार्थ के लिए अधिक कार्य करते हैं अतः वे

'विकास व्यवस्था' की अपेक्षा 'अनुरक्षण व्यवस्था' से अधिक संबद्ध हैंए जिसके फलस्वरूप वे राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण करने में असफल रहे हैं अथवा द्रुतगामी आर्थिक नीतियों और सामाजिक कार्यक्रमों को विकसित करने और उनके क्रियान्वयन में सफल नहीं रहे हैं। मार्क्सवाद के लेनिनवाद चर के रूप में वे जनता को परमाणु की तरह पृथक व्यक्तियों से उन चेतन और अनुशासित अभिकर्ता, जो पूर्ण सामाजिक परिवर्तन कर सकेंए के रूप में बदलने में असफल रहे हैं। यह भी सत्य है कि यदि हमारा देश अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा है तो कारण यह है कि राजनैतिक अभिजन अपने समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अनेक प्रकार से बाधक ही सिद्ध हुए हैं।[8]

उत्तर प्रदेश में युवा राजनीति का स्वरूप पारंपरिक छात्रसंघ राजनीति तक सीमित नहीं है, अपितु पिछले अनेक वर्षों में सरकारी भर्तियों में निलंबन, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, परीक्षा.पत्र लीक, परिणामों में देरी तथा चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर युवाओं द्वारा व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन आदि भी शामिल हैं। प्रदेश की छात्र राजनीति का इतिहास अत्यंत समृद्ध एवं गौरवशाली रहा है। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे संस्थाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आपातकाल के विरोध तक महती भूमिका अदा की हैए परन्तु 2006 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लिंगदोह समिति की सिफारिशों के लागू होने के बाद अधिकांश विश्वविद्यालयों में, छात्रसंघ के चुनाव, अनिश्चितकाल के लिए बंद या बाधित हो गए हैं। छात्रसंघ चुनाव, जिसे 'रचनात्मक नेतृत्व का नर्सरी' और, राजनीति की पहली पाठशाला' भी कहा जाता है, इसके स्थगन से विश्वविद्यालयों में **'लोकतांत्रिक रिक्तता**' पैदा हो गई है। प्रदेश में युवा राजनीति को केवल चुनावी राजनीति अथवा छात्र आंदोलनों तक सीमित करके नहीं समझा जा सकताए अपितु यह नागरिक समाज की व्यापक लोकतांत्रिक। भागीदारी का हिस्सा है। बेरोजगारी, रोजगार की अनिश्चितता तथा अवसरों की असमानता, युवाओं की राजनीतिक चेतना को नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करती है और यही चेतना लोकतांत्रिक सहभागिता के माध्यम से राज्य की नीतियों, प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं सार्वजनिक विमर्श आदि को निरंतर प्रभावित करती है।

रचनात्मक शक्ति: सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक विमर्श:

नागरिक समाज केवल अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन का निष्क्रिय दर्शक नहीं होता अपितु वह अपनी राजनीतिक क्षमता यथा. निरंतर राजनीतिक सत्ता की आलोचना, सहभागिता, सक्रियता, जागरुकताए सार्वजनिक विमर्श, शान्तिपूर्ण धरना प्रदर्शन, जनमत निर्माण, सामाजिक आंदोलनों, नीति निर्माण में सक्रिय सुझाव आदि के माध्यम से सत्ता को निरंतर नियंत्रितए मर्यादितए संतुलित एवं अनुशासित रखती हैए यही नागरिक समाज की रचनात्मक शक्ति है। इस प्रकार रचनात्मक शक्ति **राजनीतिक भागीदारी में मानव पूंजी** पर जोर देता है। हन्ना अरेंट ने यूनानी राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होकर रचनात्मक शक्ति की नई अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें राजनीति का वास्तविक स्वरूप नागरिकों की सार्वजनिक क्रिया (Action) और सार्वजनिक क्षेत्र (Public Realm) में सक्रिय भागीदारी से निर्मित होता है। जब नागरिक सार्वजनिक जीवन में विचार करते हैं, संवाद करते हैं और सामूहिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं, तभी लोकतंत्र जीवित रहता है।[9] युर्गेन हेबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सामूहिक कार्रवाई की संकल्पना के माध्यम से लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति को स्वतंत्र एवं तर्कपूर्ण सार्वजानिक संवाद में निहित पाया। नागरिक समाज जब सरकार की नीतियों की समीक्षा करता है, वैकल्पिक सुझाव देता है और सार्वजनिक विमर्श के माध्यम से जनमत का निर्माण करता है, तब लोकतांत्रिक शासन अधिक उत्तरदायी बनता है।[10] महात्मा गांधी रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि सामाजिक परिवर्तन में सत्ता परिवर्तन के साथ नागरिक समाज के नैतिक सक्रियता एवं जनभागीदारी भी महती

भूमिका अदा करती है। जयप्रकाश नारायण ने सम्पूर्ण क्रांति के माध्यम से युवाओं और नागरिक समाज को न सिर्फ सत्ता परिवर्तन का बल्कि लोकतांत्रिक परिवर्तन का भी प्रमुख कारक माना; राम मनोहर लोहिया ने लोकतंत्र को जनभागीदारी, सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकरण से जोड़कर देखा; वहीं डॉ॰ भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकताए सामान अवसर और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र को लोकतंत्र की आधारशिला मानए अमर्त्य सेन ने भी क्षमता निर्माण सिद्धांत के माध्यम से नागरिकों की क्षमताओं के विकास एवं सार्वजनिक जीवन में सहभागिता पर जोर दिया। व्यवहार के स्तर पर रचनात्मक शक्ति लोकतंत्र के दैनिक संचालन में दिखाई पड़ता है। जब नागरिक समाज द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना, सूचना के अधिकार का प्रयोग, जनसुनवाई में भागीदारीए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनए न्यायालयों का सहाराए सामाजिक आंदोलनों का संचालनय तब वे लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी बनाते हैंए जो शासन व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती है एवं लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक पारदर्शी एवं जनोन्मुख बनाती है।

इस प्रकार रचनात्मक शक्ति, ग्रेबियल आमंड एवं सिडनी वर्बा सुषुप्त श्वान सिद्धांत (नागरिकों की निष्क्रियता राजनीतिक सत्ता के लिए आदर्श स्थिति होती है) के विपरीत, लोकतंत्र में मानवीय पूंजी अर्थात् नागरिकों की राजनीतिक उद्यमिता पर जोर देती है।

बेरोजगारीए युवा राजनीति एवं रचनात्मक शक्ति का संबंध:

नितिन बिष्ट और फाल्गुनी पटनायक ने अपने अध्ययन में पाया कि भारतीय युवा श्रम बाजार के संदर्भ में सामान्य शिक्षा और रोजगार के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। सामान्य शिक्षा में वृद्धि के साथ कार्य भागीदारी दर में गिरावट इस परिकल्पना को मान्य नहीं करती कि युवाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि के साथ रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। शिक्षा, रोजगार और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के बीच अंतर्संबंध युवा श्रम बाजार की मांग के अनुरूप सुदृढ़ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मानव पूंजी में निवेश की अवधारणा को उजागर करता है। समय के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं की संख्या में वृद्धि भारत के लिए शिक्षित युवाओं का भंडार प्रस्तुत करती है। दूसरी ओर, यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी सवाल उठाता है, जो एसडीजी के लक्ष्य 4.4 में निर्धारित उचित कार्य संकेतकों से परिपूर्ण समान रोजगार अवसर सृजित करके इन शिक्षित युवाओं की क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रही है। कुल जनसंख्या में युवाओं की वर्तमान हिस्सेदारी (27 प्रतिशत) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर प्रतीत होती है, हालांकि, इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए नियमित और गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने की आवश्यकता है। युवाओं में श्रम बल और कार्यबल भागीदारी दरों में कमी उच्च शिक्षा प्राप्ति की ओर प्रतिमान में बदलाव को दर्शाती है, जो दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए सहायक है। हालांकि, दूसरी ओर, यह चिंता का विषय भी है जब अध्ययन में शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी का उच्चतम स्तर पाया जाता है।[11] देश एवं प्रदेश में ऐसे अनेक छात्र आधारित आंदोलन हुए, जिसने राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। 1974 में जयप्रकाश नारायण का छात्र आंदोलन जिसमें छात्रों की व्यापक भागीदारी रही, भारतीय राजनीति में बड़ा परिवर्तन किया, 1973-74 गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन जिसमें छात्रों ने भ्रष्टाचार और महंगाई के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन शुरू किया, जिससे प्रभावित होकर राज्य सरकार को इस्तीफा देना पड़ा एवं राष्ट्रीय राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा, 1979-85 असम आंदोलन ने असम समझौता एवं छात्र नेतृत्व को सत्ता में आने का अवसर दिया, 1990 का मंडल विरोधी छात्र आंदोलन जिसने राष्ट्रीय पटल पर आरक्षण संबंधी एक नई बहस छेड़ दी और भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय को एक नया आयाम दिया, 2012 का निर्भया आंदोलन, जिसमें छात्रों एवं युवाओं की भागीदारी रही, आपराधिक कानून संशोधन (2013) एवं महिला सुरक्षा पर नीतिगत परिवर्तन लाया, 2026 का नीट परीक्षा सुधार आंदोलन से जुड़ा काकरोच

जनता पार्टी का आंदोलन जिसमें छात्रों की परीक्षा पारदर्शिता एवं पेपर लीक के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया, जिसके दबाव में राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा एवं शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अलग.अलग समय पर हुए छात्र आंदोलनों के विभिन्न चरणों ने प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, 2018-22 का शिक्षक भर्ती आंदोलन, 2024 का यूपीपीएससी आरओ/एआरओ आंदोलन एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक आंदोलन में छात्रों की सक्रियता ने रचनात्मक शक्ति को प्रभावित किया।

बेरोजगारी का युवा राजनीति और रचनात्मक शक्ति से गहरा संबंध है। जब रोजगार के अवसर सीमित रहें, भर्ती प्रक्रिया लंबित रहे एवं संस्थागत पारदर्शिता प्रभावित रहे, तब ऐसे में युवाओं में राजनीतिक चेतना, और सक्रियता बढ़ती है। यह युवा सक्रियता लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी। यदि राज्य संवाद, पारदर्शिता, सूचिता एवं संवैधानिक उपायों के माध्यम से युवाओं के मांगों का समाधान करती है तो यही युवा ऊर्जा लोकतांत्रिक वैधता, नीतिगत नवाचार, संस्थागत उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक सुधार आदि को सुदृढ़ करती है। इसके विपरीत, यदि संवाद के लोकतांत्रिक मार्ग अवरुद्ध हो जाए तो यही युवा ऊर्जा निराशा, अविश्वास, कुंठा, विद्रोह, राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक उदासीनता आदि का कारण बनती है।[12] बेरोजगारी का युवा राजनीति और रचनात्मक शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा; इसका सबसे बड़ा कारक राज्य सरकार की प्रतिक्रिया एवं नागरिक समाज की सक्रियता। राज्य सरकार सही समय पर उचित कार्रवाई करती है तो रचनात्मक शक्ति एवं राजनीति में युवाओं की भागीदारी सकारात्मक रूप से बढ़ेगीए जबकि इसके विपरीत राज्य सरकार बेरोजगारी एवं युवाओं के के प्रति उदासीन रहती है तब ऐसे में इसका प्रभाव नकारात्मक पड़ेगा और यह राजनीतिक ध्रुवीकरणए विद्रोह एवं क्रांति का मार्ग भी धारण कर सकता है।

तालिका 3रू बेरोजगारी एवं युवा राजनीति का रचनात्मक शक्ति पर प्रभाव

समस्या	बेरोजगारी (साकारात्मक प्रभाव)	बेरोजगारी (नकारात्मक प्रभाव)
प्रतिक्रिया	सरकार की सक्रियता + युवा राजनैतिक चेतना	सरकार की उदासीनता + युवा निराशा एवं कुंठा
प्रभाव	राजनीतिक उद्यमिता (लोकतांत्रिक सहभागिता, जनमत निर्माण, नीतिगत सुधार, लोकतांत्रिक वैधता)	राजनीतिक बेरोजगारी/अलगाव (संस्थाओं पर भी विश्वास, राजनैतिक ध्रुवीकरण, अलोकतांत्रिक मार्ग, विद्रोह एवं क्रांति)
सिद्धांत	1.वर्ग चेतना (काल मार्क्स) 2.सहभागी राजनीतिक संस्कृति (आमंड एवं वर्बा) 3.राजनीतिक एवं सामाजिक उद्यमिता (जोसेफ शुम्पीटर)	1. अलगाव का सिद्धांत (कार्ल मार्क्स) 2. तनाव या एनोमी सिद्धांत (राबर्ट के मॉर्टन) 3. सुषुप्त श्वान (आमंड एवं वर्बा)
परिणाम	रचनात्मक शक्ति का विस्तार एवं स्वस्थ युवा राजनीति	रचनात्मक स्थिति का ह्रास एवं अस्वस्थ युवा राजनीति

निष्कर्ष:

प्रस्तुत शोध.पत्र से यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी केवल एक आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, एवं राजनीतिक समस्या भी है। बेरोजगारी एवं युवा राजनीति किस प्रकार रचनात्मक शक्ति को प्रभावित करती है?ए इसके दो मुख्य कारक हैं।पहला नागरिक समाज की सक्रियता एवं राज्य सरकार के प्रतिक्रिया। प्रदेश में बेरोजगारी होने के बावजूद, यदि नागरिक समाज मुख्य रूप से युवा आंदोलनित नहीं होते हैंए विरोध प्रदर्शन नहीं करते हैं अर्थात। सक्रिय नहीं होते हैं एवं राज्य सरकार कोई उचित कार्रवाई नहीं एवं उदासीन बनी रहती हैए ऐसे में रचनात्मक शक्ति का ह्रास होगा। सैमुअल हंटिंगटन (संस्थागत क्षरण)ए जुर्गेन हेबरमास (वैधता का संकट) और राबर्ट मर्टन (तनाव सिद्धांत) के आलोक में यह स्थिति राजनीतिक बेरोजगारी को जन्म देती है। ऐसे में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर से युवाओं का विश्वास टूटता है, जिससे वे राजनीतिक ध्रुवीकरण और अलोकतांत्रिक मार्गों और उग्रवाद की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप रचनात्मक शक्ति का गंभीर ह्रास होता है।

इसके विपरीत, बेरोजगारी से प्रभावित युवा सक्रिय होकर विभिन्न स्रोतों के माध्यम से मुखर होते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, आंदोलित होते हैं एवं राज्य सरकार समय रहते सकारात्मक कार्रवाई करती हैए तब ऐसी स्थिति में रचनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है। जो स्वस्थ एवं उद्यमी राजनीति को बढ़ावा देता है। जो यह प्रदर्शित करता है कि हन्ना अरेंट की सार्वजनिक क्रिया (Action), जुर्गेन हेबरमास के सार्वजनिक क्षेत्रए महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमए जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांतिए लोहिया की जनभागीदारी, डॉ आंबेडकर की संवैधानिक लोकतंत्र एवं अमर्त्य सेन की क्षमता निर्माण के आलोक में लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल राज्य की संस्थाओं में नहीं, अति नागरिक समाज की सक्रिय जागरूकता और उत्तरदायी भागीदारी में निहित होती है।

उत्तर प्रदेश के आलोक में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि रचनात्मक शक्ति में वृद्धि हुई है या उसमें गिरावट आयी है। प्रदेश में बेरोजगारी, भर्ती अनियमितताओं और पेपर लीक जैसी घटनाओं के बार.बार घटित होने के कारण युवाओं की लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक सक्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो इस बात का प्रमाण है कि नागरिक समाज की रचनात्मक शक्ति में वृद्धि हुई है, किंतु इसका दूसरा पक्ष कहता है कि युवाओं के बार बार आंदोलित होने से राजनीतिक संस्थाओं में अविश्वासए गहरा अलगाव और राजनीतिक बेरोजगारी पनपी है, जो रचनात्मक शक्ति में वृद्धि नहीं बल्कि गंभीर ह्रास की ओर संकेत करती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एवं युवा राजनीति का रचनात्मक शक्ति पर संतुलित प्रभाव पड़ा है।

सन्दर्भ सूची.

1. Census of India, 2021
2. https://censusindia.gov.in/
3. Uttar Pradesh, economic Survey 2025-26
4. https://updes.up.nic.in/?hl=en-IN
5. Giddens A. (2017). *Sociology* (8th ed. Cambridge Polity Press).
6. Lipset S. M. (1981). *Political Man : The social bases of Politics* (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
7. आहूजा रा. (2021). *भारतीय समाज* (रावत पब्लिकेशन, जयपुर)।
8. Sen A. (1999). *Development as Freedom* (New York Oxford University Press).
9. Dahl R. A. (1998). *On Democracy*, (New Haven: Yake University Press,).
10. आहूजा रा. (2021). भारतीय समाज (रावत पब्लिकेशन, जयपुर)।
11. Arendt H. (1958). *The Human Condition*, (Chicago University of Chicago Press).

12. Habermas J. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere*, (Cambridge Mit Press).
13. https://www.researchgate.net/publication/341195192_Youth_Labour_Market_in_India_Education_Employment_and_Sustainable_Development_Goals
14. Arendt H. (1958). *The Human Condition*, (University of Chicago Press)